गुजरात को स्टीम कोयले की आपूर्ति

5263. **श्री अनन्तराव देवीदासराव देशमुख** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में उद्योगों के लिए कितनी मात्रा में स्टीम कोयले का आबंटन किया गया है और 1994-95 के दौरान राज्य में कोयले की कुल मांग कितनी है;

(ख) क्या गुजरात में उद्योगों के लिए मांग के अनुसार उसी अवधि के दौरान स्टीम कोयले की आपूर्ति कर दी गयी थी; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए जाएंगे ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) कोयले की आवश्यकताओं का मूल्यांकन राज्य-वार नहीं किया जाता है । इसका मूल्यांकन पूरे देश के लिए उद्योग/क्षेत्र-वार किया जाता है । गुजरात में औद्योगिक उपभोक्ताओं को स्टीम कोयले की आपूर्ति अधिकांशत: रेल द्वारा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. से की जाती है, जोकि तत्सम्बद्ध प्रायोजन प्राधिकारियों द्वारा प्रायोजन पर आधारित है । वर्ष 1993-94 के दौरान कं. को. लि. से गुजरात को आपूर्ति किए गए स्टीम कोयले की मात्रा 2.16 लाख टन (अनंतिम) थी, जबकि कार्यक्रम 2.68 लाख टन का था । इसी प्रकार वर्ष 1993-94 के दौरान साइंकोल को प्राप्त किए गए 9.71 लाख टन के आपूर्ति किए जाने के कार्यक्रम की तुलना में इस कम्पनी से 7.27 लाख टन (अनंतिम) की आपूर्ति की गई ।

कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आपूर्ति को और अधिक किया जा सकता था लेकिन उपभोक्ताओं के द्वारा रेल कार्यक्रमों की रद्द/निलम्बन किए जाने से ऐसा नहीं किया जा सका ।

गुजरात की वर्ष 1994-95 की स्टीम कोयले की आवश्यकताओं को यथासंभव सीमा तक पूरा किया जाएगा । राज्य को स्टीम कोयले की वास्तविक आपूर्ति स्टीम कोयले एवं रेलवे वैगन दोनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है । गुजरात के अधिकांश उपभोक्ता सा. ई. को. लि. की कोरिया-रेवा कोल-फील्ड्स कोयले को प्राथमिकता देते हैं जहां से कि कोयले का प्रेषण में वृद्धि विभिन्न व्यवधानों के कारण नहीं की जा सकती है, जिसमें परिवहन संबंधी व्यवधान भी शामिल है । यदि उपभोक्ता वैकल्पिक स्रोत से कोयले के प्रेषण को तरजीह दें तो उनके प्रेषण में वृद्धि की जा सकती है । कुछ कोलियरियों को उदारीकृत बिक्री योजना के तहत रखा गया है जहां से कि औद्योगिक उपभोक्ता बिना किसी प्रायोजन के अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं ।

ललमतिया राजमहल परियोजना के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास

5264. **श्री जनार्दन यादव** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ललमतिया राजमहल परियोजना के कारण लगभग एक हजार लोग विस्थापित हो गए हैं;

(ख) क्या इन विस्थापित लोगों की पुन: बसाने के लिए सरकार की कोई योजना है; और

(ग) इन विस्थापित लोगों को फिर से कब तक बसाए जाने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) लालमटिया राजमहल परियोजना में उत्पादन योजना के आधार पर गांव तथा ग्रामवासियों के घरों का चरणबद्ध रूप में अधिग्रहण किया गया है । प्रथम चरण में, 3 गांवों को, जिसमें 399 परिवार थे, का पुनर्वास किया जाना है । व्यक्तियों की संख्या, जिनकी भूमि अधिग्रहण की गई है, की संख्या 860 है ।

(ख) और (ग) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के पास एक योजना है, जिसके अंतर्गत वे परिवार जिन्हें उनकी भूमि से विस्थापित किया गया है, का पुनर्वास चरणबद्ध रूप से करेगी । इस प्रयोजन के लिए पुनर्वास स्थल का अधिग्रहण कर लिया गया है तथा संरचनात्मक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं । विस्थापित परिवारों को घरों के निर्माण के लिए भू-खंड उपलब्ध कराए जाते हैं तथा उन्हें अन्य विस्थापित संबंधी सहयोग तथा सहायता दी जाती है । पुनर्वास लाभ, जिला प्राधिकारियों तथा जनता के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके उपलब्ध कराए जा रहे हैं । व्यक्तियों को तब तक स्थानान्तरित नहीं किया जाता है जब तक कि उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर दी जाती है और वे स्थानान्तरित होने के कारण तैयार नहीं होते हैं ।

Kittadi Jhanjra and Sonepur coal project

5265. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA : Will the Minister of COAL be pleased state :

(a) the name of the agency who prepared the project report and who approved the same in respect of Kottadi underground project, Jhanjra underground Project and Sonepur Bazari Open Caste;

(b) what is the reserve and projected capacity of the Kottadi Underground Project;

(c) what is the sanctioned cost;

(d) what is the date of approval;

(e) what is the total investment made till 31st March, 1994;

(f) what is the production capacity as on 31st March, 1994;

(g) whether it is a fact that the production capacity of the above projects is not likely to be achieved inspite of revised cost estimation and higher investment than the original sanctioned cost;

(h) if so, who is responsible for this state of affairs; and

(i) if not, why even 30 per cent of the estimated production has not been achieved even after such a large investment ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA) : (a) The original project report of Jhanjra underground project was prepared by experts from erstwhile USSR. This was elaborated by the Central Mine Planning and Design Institute Ltd. (CMPDIL). Project Report for Kottadih project was prepared by CMPDIL and the underground portion was based on the technical inputs of French Experts. The Project Report for Sonepur Bazari OCP was prepared by CMPDIL. All the Project Reports were approved by the Board of Directors of Eastern Coalfields Ltd. as well as of Coal India Ltd. Investments on all these projects were approved by the Government.